(v) एक उचित दर की दुकान के लिए कम से कम 4000 यूनिटों का आवंटन किया जाए ।

(vi) उचित दर की दुकानों को बैंक ऋण देने की व्यवस्था की जाए ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर समय-समय पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि उचित दर की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें । उनसे कहा गया है कि वे विनिर्माताओं से उन अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति स्वयं करें, जिन्हें वे उचित दर की दुकानों के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता में वितरित कर सकती हैं । इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने तथा उचित दर की दुकानों में खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होने के के कारण, उन्हें दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे हर 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान खोलने के आधार पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं । इस संबंध में छितरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में जहां इस मानदंड को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है । राज्य सरकारें, प्राप्त हुई शिकायतों की जांच के आधार पर उचित दर की दुकानों के मालिकों के खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही करती हैं । चूंकि आवश्यक वस्तुओं का कारोबार करने वाली उचित दर की दुकानें प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि वे उचित दर की दुकानों के मालिकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण सुविधाएं दिलवाने के लिए प्रबंध करें ।

सरकारी कालोनियों में सफाई

2450. श्री रामचन्द्र विकल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सरकार कालोनियों ; सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या कुछ कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस कार्य को ठेकेदारों से ठेके पर कराता है, यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह कार्य कुछ पूछताछ में "हैंड रसीद" पर भर्ती कर्मचारियों से कराया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को धक्का लगा है और इससे न केवल अनुसूचित जातियों के लोगों में बेरोजगारी ही बढ़ी है बल्कि सफाई व्यवस्था में भी गिरावट आई है ; और

(ङ) सरकार इस कार्य को ठेकेदारों से कराने की प्रथा को कब तक खत्म करने तथा इसे नियमित आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों से कराने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Inadequate pasture land near Ranthombore Park

2451. PROF. C. LA&SHMANNA: SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that a number of villages surrounding the Ranthombore Park area in Rajasthan have not adequate pastures lawn for their cattl$_e$ numbering about 40, 000; and

(b) if so, whether Government have take$_n$ any measures to provide adequate fodder to the villages for their cattle so that the Ranthombore National Park area is not damaged by the villagers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Rajya Sabha as soon as it is received.

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति

2452. श्री रामचन्द्र विकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: कितनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार श्रमिकों को कार्य सुलभ कराने के लिये कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) सातवीं योजना के डाक्यूमेंट के अनुसार, सातवीं योजना के आरम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुमान 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 4.97 मिलियन लगाया गया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सामान्य स्तर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कुल व्यक्तियों की तुलना में बेरोजगारों का प्रतिशत 1983 में किए गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें दौर से मिलता है, जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की पत्रिका अर्थात् "सर्वेक्षण वाल्यूम 9–संख्या 4 (अप्रैल, 1986) में प्रकाशित किया गया है। इस पर आधारित विभिन्न राज्यों में सीमान्त श्रमिकों सहित सामान्य स्तर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है (नीचे देखिये)

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के संदर्भ में चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 (अक्तूबर, 1986 तक) के दौरान उपयोग में लाई गई नकद निधियों और खाद्यान्नों तथा सृजित किए गए रोजगार को दर्शाने वाला विवरण–2 संलग्न है।

विवरण–1

सामान्य स्तर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष और उससे ऊपर के आयु के कुल व्यक्तियों में बेरोजगारों का प्रतिशत

अवधि : जनवरी–जून, 1983 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 38वां दौर)

राज्य	पुरुष	महिलाएं
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1.18	0.58
2. असम	1.51	0.25